अपनी बात

पंचेन लामा की रिहाई हेतु चीन सरकार से अपील

तिब्बत के ग्यारहवें पंचेन लामा गेदुन छोक्यी नीमा की रिहाई की मांग एक अंतरराष्ट्रीय मांग बन चुकी है। परमपावन दलाई लामा जी ने 14 मई 1995 को पंचेन लामा के पुनर्जन्म और अवतार के रूप में उन्हें मान्यता प्रदान की थी। इसके तीन दिन बाद ही चीन सरकार ने उन्हें उनके परिजनों समेत गिरफ्तार कर लिया। तब से चीन सरकार उनके बारे में कुछ भी नहीं बता रही है। उस समय वे महज छह साल के छोटे बालक थे। अभी गत 25 अप्रैल को पंचेन लामा के जन्म दिन के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनमें संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य सभी मानवाधिकार संगठनों से अपील की गई है कि वे साम्राज्यवादी चीन सरकार पर दबाव डालें और पंचेन लामा की उनके परिजनों समेत रिहाई सुनिश्चित करें।

पंचेन लामा तिब्बत के महत्वपूर्ण धर्मगुरू हैं। चीन सरकार द्वारा उनकी गिरफ्तारी अंतरराष्ट्रीय कानून, लोकतंत्र तथा मानवीय आदर्शों पर कुठाराघात है। उचित यही है कि चीन सरकार तिब्बती आंदोलनकारियों तथा अन्य तिब्बत समर्थकों की मांग का आदर करे और पंचेन लामा को उनके परिजनों समेत यथाशीघ्र अवैध हिरासत से मुक्त कर दे।

तिब्बत में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। मानवाधिकारों का हनन जारी है। चीन सरकार वहाँ प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद कर रही है तथा पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। तिब्बत में चीन सरकार की विनाशकारी नीति नहीं रोकी गई तो पूरे विश्व, विशेषकर एशियाई देशों को कई गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल 2015 का विनाशकारी भूकंप भी इसी का प्रमाण है। नेपाल, तिब्बत, भारत तथा भूटान इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। दलाई लामा तथा निर्वासित तिब्बत सरकार ने पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदनायें व्यक्त की हैं। तिब्बत समर्थक अन्य सभी संगठन भी इस दुखद घड़ी में पीड़ितों के साथ हैं। लेकिन भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदायें नहीं हों, इसके लिए हमें पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करना होगा। सबसे बढ़कर चीन सरकार की जिम्मेदारी है कि वह तिब्बत के तथाकथित विकास के नाम पर वहाँ प्राकृतिक असंतुलन तथा प्रदूषण मत बढ़ाये। चीन भी संयमित–संतुलित विकास की नीति अपनाए।

इसी अप्रैल 2015 में चीन के राष्ट्रपति शी जिंपिंग ने पाकिस्तान का दौरा किया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ऐसे समझौते भी किए हैं, जिनसे भारतीय हितों को गंभीर खतरा है। मई 2015 में संभावित अपनी चीन यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का सवाल जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। चीन सरकार भारत को लगातार कमजोर करने तथा अपमानित करने की नीति पर चल रही है। राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ाकर चीन से संबंध सुधारना आत्मघाती होगा। सन् 1962 में भारत के साथ यही हुआ।

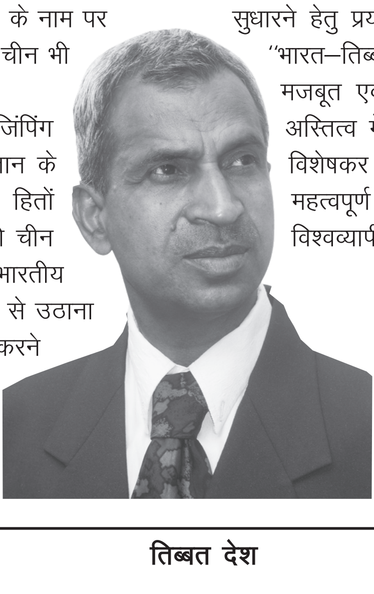

चीन से संबंध सुधारने के नाम पर भारत ने स्वतंत्र तिब्बत देश को चीन का अभिन्न अंग मान लिया। ''हिन्दी–चीनी भाई भाई'' के नारे लगने लगे। सफेद कबूतर उड़ाए जाने लगे। ''पंचशील'' समझौता हो गया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ भारत पर चीन का आक्रमण। भारत की पराजय। नेहरू जी के लिए तो परिणाम प्राणघातक सिद्ध हुआ। इसलिए हम उस भूल को दुहराने से बचें। वह मौलिक भूल थी तिब्बत की आजादी का चीन के हाथों समर्पण। तब अनेक भारतीय राजनेताओं एवं विचारकों ने प्रधानमंत्री नेहरू जी को सावधान किया था। उन्हें बताया था कि तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के बाद चीन का अगला शिकार भारत ही होगा। वे सभी भविष्यवाणियाँ सही साबित हुई हैं।

भारत को चीन के साथ संबंध सुधारते समय तिब्बत के प्रश्न को ठीक से उठाना होगा। इस समय उपयुक्त परिस्थिति है। दलाई लामा तथा निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री सिक्योंग डॉ. लोबसंग संग्ये तिब्बत की पूर्ण आजादी की मांग छोड़ चुके हैं। वे चीनी संविधान के अनुरूप तिब्बत को ''वास्तविक स्वायत्तता'' की मांग कर रहे हैं। तिब्बत समर्थक अधिकांश संगठन चाहते हैं कि तिब्बत पूरी तरह आजाद हो जाए, लेकिन तिब्बती नेतृत्व केवल ''वास्तविक स्वायत्तता'' से ही संतुष्ट है। भारत द्विपक्षीय वार्ता के दौरान चीन सरकार पर तिब्बती नेतृत्व की मांग को स्वीकारने हेतु दबाव बढ़ाये। भारत–चीन संबंधों में सुधार हेतु तिब्बत संकट का हल आवश्यक रूप से करना होगा। आशा की जानी चाहिए कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चीन सरकार के समक्ष इन जरूरी मुद्दों को सफलापूर्वक उठाएगी।

तिब्बत समस्या का समाधान होने से सर्वाधिक लाभ भारत को होगा। प्रसिद्ध विचारक डॉ. राम मनोहर लोहिया इसीलिए कहते थे कि तिब्बती आंदोलनकारियों का साथ देकर हम भारतीय तिब्बतियों के ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। यह हमारा अपना ही कार्य है। तिब्बत को चीन के चंगुल में फँसाकर हमने गलती की थी। अब तिब्बत की दशा को सुधारने हेतु प्रयास हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। ऐतिहासिक काल से ''भारत–तिब्बत सीमा'' का अस्तित्व रहा है। तब भारत–चीन संबंध मजबूत एवं विश्वसनीय होते थे। जब से ''भारत–चीन सीमा'' अस्तित्व में है, तभी से भारतीय राष्ट्रीय हित तथा विश्व शांति, विशेषकर एशिया में शांति खतरे में है। अतः भारतीय नेतृत्व की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि तिब्बत समस्या के समाधान हेतु वह विश्वव्यापी संघर्ष को रचनात्मक सहयोग प्रदान करे। ◆

प्रो0 श्यामनाथ मिश्रा
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खेतड़ी (राज.)
ek-&9829806065] 8764060406
E-mail & Facebook :- shyamnathji@gmail.com

परमपावन दलाई लामा ने धर्मशाला में आर्कबिशप डेसमंड टुटु का स्वागत किया

(तिब्बतरीव्यू डॉट नेट, 20 अप्रैल, धर्मशाला)

कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे आर्कबिशप डेसमंड टुटु और उनकी बेटी मफो के साथ परमपावन दलाई लामा। टुटु धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के सात दिन के दौरे पर 18 अप्रैल, 2015 को पहुंचे। फोटो साभारः ओएचएचडीएल

तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक नेता परमपावन दलाई लामा ने 18 अप्रैल को कांगड़ा एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका के सेवानिवृत्त राजनीतिज्ञ आर्कबिशप डेसमंड टुटू का स्वागत किया। दोनों नोबेल पुरस्कार विजेता और 'आध्यात्मिक भाई' 'बुक ऑफ ज्वॉय' नाम से एक पुस्तक में 'असल आंतरिक खुशी' की तलाश पर संवादों की श्रृंखला का प्रकाशन करेंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए परमपावन दलाई लामा ने आर्कबिशप की तारीफ करते हुए उन्हें एक 'वास्तव में अच्छा व्यक्ति' बताया और उनके आने पर खुशी जताई।

इस अवसर पर आर्कबिशप टुटू ने दो साल पहले अपने 80वें जन्म दिन पर दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा दलाई लामा को वीजा देने से इनकार करने के मामले का हवाला देते हुए कहा, "मैं अपने प्रिय दोस्त को साथ पाकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूं। अक्सर बहुत–सी चीजें और लोग हमें दूर रखते हैं, लेकिन हमारे बीच जो प्यार है और ईश्वर के इस ब्रह्मांड की अच्छाई की वजह से हमारा मिलना सुनिश्चित होता है।"

ऐसे समय में जब दलाई लामा के भी 80वां जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही है, द गार्जियन में 15 अप्रैल को छपी खबर के अनुसार दोनों नेता "गहरे संवाद और हंसी–मजाक में अपना समय बिताएंगे। दोनों इस बात पर अपने अनुभवों को साझा करेंगे कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए खुशी कैसे तलाशी जाए।" उनकी यह चर्चा किताब का आधार बनेगी और इस जोड़े ने लेखकों के फेसबुक पेज पर जनता से खुशी और आनंद के बारे में जो भी सवाल पूछे हैं, उनमें से ज्यादातर का जवाब देने की कोशिश करेंगे।

पुस्तक के प्रकाशक हचिंसन ने बताया कि यह "एक अनूठा गठजोड़ है जो लेखकों के बीच असाधारण दोस्ती को दर्शाता है। इसके सह–लेखक डाउग अब्राम्स भी होंगे जिन्होंने पिछली किताबों में टुटु के साथ काम किया है और वह इंटरव्यू करेंगे।

निर्वासित तिब्बती प्रशासन की वेबसाइट तिब्बत डॉट नेट पर 19 अप्रैल को दी गई जानकारी के अनुसार टुटु की धर्मशाला यात्रा एक हफ्ते की है। ◆

तिब्बत मंच जेएनयू द्वारा तिब्बतन रीव्यू के साथ मिलकर प्रोफेसर दावा नोर्बू के सम्मान में 7 अप्रैल को एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

आधुनिक तिब्बती अध्ययन को आगे बढ़ाने वाले प्रोफेसर को श्रद्धांजलि

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 8 अप्रैल, 2015)

स्वर्गीय प्रोफेसर दावा नोर्बू के सम्मान में 7 अप्रैल को नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रोफेसर दावा आधुनिक एकेडमिक क्षेत्रों में निर्वासित तिब्बती सरकार द्वारा तमाम स्कॉलरशिप शुरू करने के प्रणेता थे। 1970 के दशक में वह तिब्बतन रीव्यू पत्रिका के संपादक के रूप में प्रख्यात थे, बाद में वह जीवन पर्यंत जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में केंद्रीय एशियाई अध्ययन के प्रोफेसर रहे।

जेएनयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. सोपोरी इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे, जबकि दलाई लामा के नई दिल्ली स्थित प्रतिनिधि श्री तेम्पा सेरिंग ने इसकी अध्यक्षता की। बाद में दावा के स्कूल के समय के एक दोस्त ने उनके शैक्षणिक मजबूती और उत्साह तथा शुरुआती उम्र से ही जानकारी की उनकी भूख के बारे में बताया।

जब दावा नोर्बू जेएनयू में विद्यार्थी के रूप में पहुंचे, उस समय प्रोफेसर सोपा. ेरी फेकल्टी के सदस्य थे। प्रोफेसर सोपोरी ने कहा कि दावा ने रिसर्च वर्क में अपने गहरे अन्वेषण से साथियों को काफी प्रेरित किया और उनकी सराहना हासिल की थी। धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती प्रशासन के प्रमुख सिक्योंग लोबसांग सांगे ने अपने मुख्य संबोधन में बताया कि वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर दावा नोर्बू के साथ कुछ समय रह चुके थे।

दावा नोर्बू के पुत्र रिनछेन जामयांग नोर्बू ने अपने पिता के बारे में एक भावुक भाषण दिया जो अपने परिवार की गहराई से देखभाल करते थे और वह अपने शैक्षणिक लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित थे तथा अपने देश से उनका गहरा लगाव था।

संगोष्ठी के चार सत्रों में से पहले सत्र की अध्यक्षता नई दिल्ली के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो प्रोफेसर सिद्दीक वाहिद ने की और इस सत्र को प्रोफेसर दावा के कार्यों पर उनके पूर्व छात्रों द्वारा जानकारी देने पर फोकस किया गया। "तिब्बती इतिहासकार दावा नोर्बू : तर्काधार, हास्यबोध और बुद्धिमत्ता के व्यक्ति" विषय पर अपना पेपर पेश करते हुए जेएनयू में चीनी एवं चीन विद्या अध्ययन के प्रोफेसर प्रियदर्शी मुखर्जी ने स्वर्गीय प्रोफेसर की तिब्बती आंदोलन के इतिहासकार के रूप में उपलब्धियों को दर्शाया और इतिहास की उनकी वस्तुनिष्ठ आलोचना पर भी प्रकाश डाला जो कि 1959 से पहले और 1959 से बाद पिछली शताब्दी तक के दो हिस्सों में विभाजित रही है।

हैदराबाद विश्वविद्यालय में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर एम.एन. राजेश ने 'तिब्बत के साथ साइबर एनकाउंटर : एक खुला अभियान' विषय पर अपना पेपर पेश किया। उन्होंने महत्वपूर्ण लेकिन नजरअंदाज किए जाने वाले विषय साइबर सुरक्षा और साइबर उपभोक्तावाद जैसे मसलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि परंपरागत तिब्बती स्वदेशी तकनीक और जानकारी को सरकार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा पेटेंट कराकर भारी मुनाफे पर बेचा जा रहा है, जबकि साइबर स्पेस को तथाकथित ग्रेट फायर वाल ऑफ चाइना द्वारा सीमित किया जा रहा है। झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के प्रमुख डॉ. सतीश कुमार ने "भारत और चीन के संबंधों के बीच तिब्बत कारक" पर एक पेपर

पेश किया।

दूसरे सत्र का थीम था– "संस्कृति का मसला और चीन–तिब्बत जुड़ाव"। इस सत्र की अध्यक्षता जेएनयू में पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली ने की। इस अवसर पर गेशे ल्हाकडोर ने धर्मशाला स्थित लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स ऐंड आर्काइव्स पर एक डॉक्यूमेंट्री पेश किया जिसके वह निदेशक हैं। उन्होंने प्राचीन तिब्बती हस्तलिपि और शिल्पकृति के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला जिन पर चीनी तिब्बती शासन में जबर्दस्त संकट है और उन्होंने पुस्तकों, अनुसंधान केंद्र, दुनिया भर के तिब्बतविदों के बीच संवाद के द्वारा तिब्बती संस्कृति, विरासत के प्रचार में उसकी भूमिका पर भी रोशनी डाली।

निर्वासित तिब्बती प्रशासन, धर्मशाला के तहत आने वाले तिब्बत नीति संस्थान के निदेशक श्री थुबतेन सामफेल ने "चीनियों तक तिब्बतियों की पहुंच" विषय पर एक पेपर प्रस्तुत किया। उन्होंने बौद्ध धर्म, तिब्बती संस्कृति और भाषा के परिप्रेक्ष्य में चीनी और तिब्बती लोगों के बीच दोस्ती के मजबूत होते बंधन और साझा हितों के विकास पर प्रकाश डाला। उनका यह मानना था कि निर्वासित तिब्बती प्रशासन के मध्यम मार्ग नीति का बढ़ता औचित्य तिब्बत–चीन संबंधों में किसी बड़े नतीजे तक पहुंचने का संकेत दे रहा है।

तीसरे सत्र की अध्यक्षता जेएनयू के राजनीतिक अध्ययन केंद्र के पूर्व प्रोफेसर प्रोफेसर राकेश गुप्ता ने की। इस सत्र का विषय था–"तिब्बत की राजनीति और सुरक्षा के बारे में सामयिक मसलों का अध्ययन"। "चीन की विदेश नीति और भारत" विषय पर बोलने वाले प्रोफेसर कोंडापल्ली ने बीजिंग में 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद भारत एवं चीन के विकसित रिश्ते, दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के प्रति उसके रवैये से संबंधित विभिन्न बारीकियों और चीन–भारत विदेश नीतियों पर बातचीत में तिब्बत की केंद्रीय भूमिका के बारे में बताया।

प्रतिरक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के प्रोफेसर एस.डी. मुनि ने "दक्षिण एशिया में चीन से निपटने" के बारे में बोला। उन्होंने संगोष्ठी में आए लोगों को बताया कि चीन पिछले वर्षों में दक्षिण एशिया में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए किस तरह का रवैया अपना रहा है, इस इलाके में उसका भारत से हितों का टकराव किस तरह का है और भारत तथा समूचे इलाके में इस तरह के टकराव के किस तरह के सामरिक निहितार्थ हैं।

जेएनयू में अंतरराष्ट्रीय राजनीति, संगठन और निःशस्त्रीकरण के केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. येशी छोदेन ने "संयुक्त राष्ट्र में तिब्बत मसले पर एक पेपर पेश किया।" उन्होंने यह अनुभव किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में तिब्बत मसले पर ध्यानाकर्षण बढ़ रहा है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित विभिन्न प्रस्तावों की वजह से चीन सरकार पर यह दबाव पड़ा है कि वह तिब्बत में मानवाधिकारों के मसले पर अपने रवैए में बदलाव लाए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और निकायों द्वारा उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी।

संगोष्ठी के समापन सत्र की अध्यक्षता जेएनयू के सामाजिक व्यवस्था अध्ययन केंद्र की प्रोफेसर रेणुका सिंह ने की। इसमें एम.एल. सोंधी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया पैसिफिक अफेयर्स की निदेशक श्रीमती माधुरी संथानम सोंधी ने अपने पति स्वर्गीय एल.एल. सोंधी की यादों के आधार पर स्वर्गीय प्रोफेसर दावा नोर्बू के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें शुरू से ही दावा एक उत्साही नौजवान की तरह लगे।

यह संगोष्ठी जेएनयू के सोशल साइंसेज ऑडिटोरियम में हुई और इसका आयोजन यूनिवर्सिटी के तिब्बत मंच तथा तिब्बतन रीव्यू मैगजीन ने मिलकर किया था। स्वर्गीय प्रोफेसर की पत्नी रिनछेन ल्हामो ने संगोष्ठी की शुरुआत में परंपरागत तिब्बती दीप जलाया और उनके दूसरे बेटे लोंगछेन नोर्बू भी इस मौके पर उपस्थित थे। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि इस संगोष्ठी से स्वर्गीय प्रोफेसर दावा नोर्बू का सम्मान और बढ़ेगा और तिब्बत अध्ययन के क्षेत्र में उनके कीमती योगदान से विद्वानों को और कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। ◆

निर्वासित तिब्बती नेताओं ने नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए शोक जताया, प्रार्थना की और दान दिया

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 28 अप्रैल, 2015)

धर्मशाला, भारत में रहने वाले निर्वासित तिब्बती नेताओं ने नेपाल में 25 अप्रैल को आए 7.9 तीव्रता के विनाशक भूंकप से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के प्रति दुःख और शोक संवदेना जताई है। तिब्बती नेताओं ने राहत और बचाव कार्य के लिए चंदा देने की पेशकश की है।

नेपाल के प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइ. राला को लिखे पत्र में दलाई लामा ने नेपाल में बड़े पैमाने पर हुई जन–धन की हानि के लिए गहरा दुःख प्रकट किया है। उन्होंने यह उल्लेख किया कि नेपाल और तिब्बत की जनता समूचे इतिहास के दौरान पड़ोसी रही है और बहुत से तिब्बतियों ने अब भी नेपाल में शरण ले रखी है। पीड़ितों और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, "नेपाल की जनता के प्रति एकजुटता की भावना के साथ मैंने दलाई लामा ट्रस्ट से कहा है कि वह राहत और बचाव कार्यों के लिए दान दें।"

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने इस दुःखद घटना के बाद एक आपातकालीन बैठक बुलाई और 27 अप्रैल को एक विशेष प्रार्थना सभा करने तथा राहत और बचाव कार्य के लिए बीस लाख भारतीय रुपए की राशि का दान देने की पेशकश की। प्रशासन ने अपने विदेशी प्रतिनिधियों तथा बस्ती अधिकारियों से भी नेपाल में राहत कार्यों के लिए चंदा जुटाने को कहा है। निर्वासित तिब्बती संसद ने तिब्बत और भारत के भूकंप पीड़ितों और उनके परिवार जनों के प्रति भी सहानुभूति और संवेदना जताई है। ◆

चीन का तिब्बत पर 13वां श्वेतपत्र एक और दुष्प्रचार के रूप में खारिज किया गया

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 17 अप्रैल, 2015)

धर्मशाला, भारत स्थित निर्वासित तिब्बती प्रशासन ने 15 अप्रैल को चीन द्वारा जारी श्वेतपत्र को खारिज करते हुए कहा कि यह चीन द्वारा तिब्बत के मसले पर अपनी झूठी कहानी को बेचने का एक हताशाभरा कदम है। चीन ने 1990 के दशक से अब तक ऐसा 13वां श्वेतपत्र जारी किया है। इसी तरह वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कैम्पेन फॉर तिब्बत (आइसीटी) ने नवीनतम श्वेतपत्र को इस बात की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा कि चीन तिब्बती लोगो के दिल और दिमाग को जीतने में विफल हुआ है। दोनों ने चीन को यह चुनौती कि वह तिब्बत को मुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय जांच के लिए खोले और वहां बाहरी लोगों को जाने दे ताकि उसके दावों की सच्चाई का पता चल सके।

चीन पर यह आरोप लगाते हुए कि वह तिब्बत के दुखद हालात पर लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है, निर्वासित तिब्बती प्रशासन ने अपनी तिब्बत डाट नेट वेबसाइट पर हाल में जारी कई रिपोर्ट का हवाला दिया। इनमें अमेरिकी विदेश विभाग, चीन पर अमेरिकी कांग्रेस के कार्यकारी आयोग, ह्यूमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तमाम रिपोर्ट शामिल हैं, जिसमें चीन के श्वेतपत्र के दावों के विपरीत बात कही गई हैं।

तिब्बती प्रशासन ने कहा कि इन रिपोर्टों में इन बातों की विस्तार से जानकारी दी गई है कि तिब्बती जनता का किस तरह से राजनीतिक दमन, आर्थिक हाशियाकरण, सामाजिक अलगाव और सांस्कृतिक विलोपन हो रहा है तथा दुनिया की छत पर किस तरह का पर्यावरण विनाश हो रहा है।

निर्वासित तिब्बती प्रशासन नवीनतम श्वेतपत्र को अपने द्वारा पिछले साल शुरू किए गए नए स्वरूप के मध्यम मार्ग नीति आंदोलन के प्रति देर से जारी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मान रहा है। तिब्बती प्रशासन ने पिछले साल मध्यम मार्ग नीति का यह आंदोलन अंतरराष्ट्रीय समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए किया था। निर्वासित तिब्बती प्रशासन ने चीन को यह चुनौती दी कि वह श्वेतपत्र जारी करने की जगह तिब्बत को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और मीडिया के लिए खोले ताकि तिब्बत के मसले पर वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट हासिल हो सके।

श्वेतपत्र के जवाब में आइसीटी ने कहा कि चीन के 'अलगाववादी-विरोधी' अफसरशाही सत्ता समूह के लिए तिब्बत में अपनी नीतिगत विफलता की जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि सभी आरोप दलाई लामा और तिब्बत के बाहर के 'शत्रु ताकतों' पर मढ़ दिए जाएं। आइसीटी ने कहा कि श्वेतपत्र में जो गुमराह करने वाले तर्क दिए गए हैं, वह केवल चीन की विफलता को और रेखांकित ही करते हैं और तिब्बत पर अपने शासन को वैध ठहराने के मामले में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की असुरक्षा को दिखाते हैं।

आइसीटी ने चीन को इस बात की चुनौती भी दी कि वह तिब्बत में स्वतंत्र प्रेक्षकों, पत्रकारों और राजनयिकों को जाने दे और यह जांचने दे कि क्या तिब्बती लोगों की हालत वास्तव में उसी तरह से अच्छी है जैसा कि उसने श्वेतपत्र में दावा किया है। ◆

तिब्बती संगठन ने चीन के कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट के खिलाफ दुनिया भर में अभियान चलाया

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 26 अप्रैल, 2015)

न्यूयॉर्क मुख्यालय वाले स्टूडेंट्स फॉर अ फ्री तिब्बत (एसएफटी) ने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और स्कूलों में बढ़ते जा रहे चीन के कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट के नेटवर्क के खिलाफ 24 अप्रैल को एक अंतरराष्ट्रीय अभियान शुरू किया। हेराल्डस्कॉटलैंड डॉट कॉम की खबर के अनुसार "अकादमिक स्वतंत्रता की रक्षा करें-कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट को ना कहें" के साथ यह अभियान तब शुरू हुआ है, जब अमेरिका, कनाडा और स्वीडन के कई बड़े विश्वविद्यालयों ने इस इंस्टीट्यूट को बाहर कर दिया है, इस चिंता की वजह से कि यह दुष्प्रचार के एक साधन की तरह काम कर रहा है।

चीन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह धन और शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट को एक दुष्प्रचार के साधन की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है, इसके द्वारा अकादमिक स्वतंत्रता सीमित की जा रही है और उन विचारों पर रोक लगाई जा रही है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हैं। दिखाने के लिए कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट में चीनी संस्कृति और भाषा की पढ़ाई होती है। असल में इस इंस्टीट्यूट के लिए चीन जिन शिक्षकों को भेजता है उन्हें तिब्बत, हांगकांग और ताइवान जैसे मसलों पर पार्टी की विचारधारा के अनुसार चलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और मेजबान संस्थान भी इस डर से एक तरह का सेल्फ-सेंसरशिप लागू कर देता है कि चीन नाखुश न हो जाए।

इस तरह के दबाव का उदाहरण देते हुए एसएफटी ने बताया कि कनाडा के एक तिब्बती विद्यार्थी को अधिकृत तिब्बत के राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन करने से रोक दिया गया ताकि चीनी धन भेजने वाले लोग नाराज न हो जाएं। उस विद्यार्थी तेनजिन डेछेन ने कहा, "चीन सरकार के दमन की वजह से ही मेरा परिवार तिब्बत से भाग निकला था। मैंने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि वे यहां कनाडा में मेरे अपने विश्वविद्यालय में कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट के द्वारा मेरी आवाज को बंद करने का रास्ता निकाल लेंगे। मुझे आशंका है कि कंफ्यूशियस इंस्टीट्यूट के मेजबान विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले दुनिया भर में तमाम विद्यार्थियों को एक सेंसर्ड शिक्षा प्रणाली के जोखिम के हवाले छोड़ दिया जा रहा है। ◆

दलाई लामा के पुनर्जन्म पर नियंत्रण की चीन की सनक से तिब्बत पर उसकी नीतियों का भांडा फूट रहा है

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 2 अप्रैल, 2015)

नई दिल्ली में 31 मार्च, 2015 को आयोजित एक चर्चा में परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि श्री तेम्पा सेरिंग, जेएनयू के प्रोफेसर आनंद कुमार, तिब्बतविद डॉ. जयदेव रानाडे और गेशी दोरजी दामडुल। फोटो साभारः टाशी नोर्बू/आइटीसीओ

मौजूदा दलाई लामा के पुनर्जन्म पर नियंत्रण कायम करने की चीन की दृढ़ता असल में उसकी यह स्वीकारोक्ति है कि 50 साल के शासन के बाद भी वे तिब्बत की समस्या को हल करने या तिब्बती जनता का दिल जीतने में विफल रहे हैं। सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस ऐंड स्ट्रेटेजी के अध्यक्ष श्री जयदेव रानाडे ने नई दिल्ली में 31 मार्च को यह बात कही। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में "चीन दलाई लामा का पुनर्जन्म क्यों चाहता है : मसले एवं चुनौतियां" विषय पर आयोजित एक चर्चा में रानाडे ने यह बात कही।

उन्होंने चीन द्वारा दलाई लामा के पुनर्जन्म के मसले पर अजीब से तर्क को उनकी नीतियों की विफलता की स्वीकारोक्ति और इस बात की स्वीकारोक्ति माना कि तिब्बत का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है।

चीन ने चीनी संसद, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के मार्च, 2015 में आयोजित सालाना सत्र के दौरान इस बात को दोहराया था कि मौजूदा दलाई लामा के निधन के बाद वह उनके पुनर्जन्म को स्थापित करेगा। चीन ने मौजूदा दलाई लामा पर यह आरोप लगाया था कि वह धर्म को बिगाड़ रहे हैं, यह कहते हुए कि इस मसले पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को है।

चीन में अल्पसंख्यक मामलों को देखने वाले शीर्ष अधिकारी झू वेइकुन ने कहा, "दलाई लामा के पुनर्जन्म या इस वंश परंपरा के अस्तित्व को खत्म करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार चीन की केंद्रीय सरकार के पास है।" वेइकुन अपनी अल्पसंख्यक विरोधी और धर्म विरोधी नीति के लिए जाने जाते हैं।

चर्चा में शामिल होते हुए तिब्बत हाउस के निदेशक गेशे दोरजी दामदुल ने कहा, "साम्यवाद में पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत नहीं है।" उन्होंने कहा, "उच्च ज्ञानी लामाओं का पुनर्जन्म एक तिब्बती बौद्ध अवधारणा है और उच्च लामा अपने पूववर्ती जीवन के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं, इसलिए तार्किक रूप से देखें तो यदि तिब्बत समस्या नहीं सुलझती है तो अगले दलाई लामा का पुनर्जन्म चीन के बाहर हो सकता है।"

दलाई लामा के नई दिल्ली स्थित प्रतिनिधि श्री पेम्पा सेरिंग ने कहा कि चीन ने जब अपने द्वारा लाए गए 11वें पंचेन लामा को स्थापित करने की कोशिश की तो वह उसमें बुरी तरह विफल हुआ क्योंकि तिब्बती जनता अब भी उन्हें 10वें पंचेन लामा का वास्तविक अवतार मानने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि इसी तरह चीन 15वें दलाई लामा के मामले में भी विफल रहेगा और इस मसले का समाधान होना चाहिए।

इस चर्चा की अध्यक्षता कर रहे जेएनयू के प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा कि चीन द्वारा दलाई लामा के पुनर्जन्म के हर पहलू पर नियंत्रण की चीन की दृढ़ता के बारे में सवाल उठाते समय हर किसी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि तिब्बत के बारे में सोचें और इसके बारे में बात करें। इस चर्चा और इसके बाद सवाल–जवाब सत्र में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों, रिटायर्ड सेना अधिकारियों, नई दिल्ली स्थित विदेशी दूतावासों के राजनीतिक अधिकारियों, विभिन्न थिंक टैंक के प्रतिनिधियों और जेएनयू एवं दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्वानों सहित 80 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया।

इस चर्चा का आयोजन तिब्बतन रीव्यू पत्रिका के साथ मिलकर नई दिल्ली स्थित भारत–तिब्बत समन्वय केंद्र ने किया था। ◆

दलाई लामा का 80वां जन्मदिन मनाने आए टुटु ने युवा तिब्बतियों को दिया प्रोत्साहन

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 25 अप्रैल)

परमपावन के 80वें जन्म दिन का उत्सव मनाने के लिए तिब्बती चिल्ड्रन्स विलेज स्कूल (टीसीवी), धर्मशाला में 23 अप्रैल, 2015 को आयोजित समारोह में मोमबत्ती बुझाते हुए आर्कबिशप डेसमंड टुटु, दो विद्यार्थी और परमपावन दलाई लामा। फोटोः तेनजिन छोजोर/ओएचएचडीएल

वैसे तो यह संभव होता नहीं दिख रहा और दमन की कड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इसके बावजूद निश्चित रूप से तिब्बती एक दिन अपने स्वाधीन देश में वापस जाएंगे। धर्मशाला में 23 अप्रैल को दोपहर अपर टीसीवी स्कूल में विद्यार्थियों और आम जनता को संबोधित करते हुए आर्कबिशप डेसमंड टुटु ने यह बात कही। आर्कबिशप 18 अप्रैल को धर्मशाला पहुंचे थे, दलाई लामा के साथ मिलकर "बुक ऑफ ज्वाय" प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए और टीसीवी में यह आयोजन तिब्बती आध्यात्मिक नेता का 80 वां जन्मदिन मनाने के लिए किया गया था। असल में दलाई लामा 6 जुलाई, 2015 को 80 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन उनके 80वें जन्मदिन के कार्यक्रम अभी से शुरू हो गए हैं।

टुटु ने कहा कि उनका अपना देश दक्षिण अफ्रीका भी बहुत वर्षों तक अन्याय और दमन की व्यवस्था का सामना कर रहा था और उसके कई नेता तथा युवा लोग एक हताशा जैसी स्थिति में निर्वासन में रह रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा, "फिर भी यह हुआ" नेल्सन मंडेला का परिवार रॉबेन द्वीप से 1995 में घर लौटा और तमाम दूसरे लोगों को भी रिहा किया गया तथा बहुत से लोग निर्वासन से अपने घर आए।

उन्होंने भारत सरकार तथा यहां की जनता का धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपनी बांहें फैलाकर तिब्बती जनता का स्वागत किया, क्योंकि "वे हमारे लिए एक ऐसे महान खजाने का संरक्षण कर रहे हैं जो खत्म हो सकता था।" उन्होंने युवा तिब्बतियों को उत्साहित करते हुए कहा, "देखो आप कितने सुंदर हो! एक दिन आप तिब्बत की सड़कों पर नृत्य और गायन करोगे।"

उन्होंने कहा, "एक दिन, आप सब अपने प्रिय तिब्बत को देखोगे। आप वहां चल रहे दमन से मुक्त हो जाओगे। और चीन सरकार यह खोज कर लेगी कि स्वाधीनता वास्तव में दमन से ज्यादा सस्ता है।"

इस दौरान तीन विद्यार्थियों ने अपनी भावनात्मक कहानियों और बहुत कम उम्र में चीनी शासन वाले तिब्बत में सब कुछ छोड़कर भारत में अध्ययन के लिए आने के बारे में अपने अनुभव बताए। टुटु की बेटी एमफो ने ऐसी एक छात्रा को जाकर गले लगाया और सांत्वना दिया। दलाई लामा का 80वें जन्म दिन का उत्सव मनाते हुए बच्चों ने एक गीत गाया और इसके बाद एक तिब्बती प्रस्तुति हुई– 'यदि आप खुश हैं और आप जानते हैं तो ताली बजाइए ना।'

दलाई लामा के एक संक्षिप्त भाषण के बाद टुटु ने बोला और इसके बाद दोनों हस्तियों ने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इसके बाद 'वी आर द वर्ल्ड' गीत गाया गया जिसमें टुटु उठ खड़े हुए और संगीत के साथ थिरकने लगे। इसके बाद उन्होंने माइक उठा लिया और 'हैप्पी बर्थडे टु हिज हॉलिनेस' गाने में सबकी अगुवाई करने लगे। इस दौरान मोमबत्तियों से सजा एक बड़ा सा केक लाया गया। उन्होंने बच्चों को परमपावन के साथ मिलकर मोमबत्तियां बुझाने के लिए बुलाया। कार्यक्रम के अनुसार दलाई लामा और टुटु को 24 अप्रैल को पुस्तक पर अंतिम चर्चा करनी थी और टुटु को 25 अप्रैल को वापस जाना था। ◆

दलाई लामा ने जापान का दो हफ्ते का दौरा संपन्न किया

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 16 अप्रैल, 2015)

तिब्बत के निर्वासित आध्यात्मिक नेता, दलाई लामा ने 13 अप्रैल को जापान का दो हफ्ते का बहुप्रशंसित दौरा संपन्न किया, जिसमें उन्होंने जापानी वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, डॉक्टरों, विभिन्न देशों से आए बौद्ध समुदाय के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता से मुलाकात और संवाद किया। दौरे के अंतिम दिन वह अलग से तिब्बतियों के एक समूह और ताइवान से आए एक बड़े जनसमूह से मिले। उन्होंने तिब्बतियों को अपने नस्लीय विशेषताओं का बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर बताया जो चीजों को दुरुस्त करने के उद्देश्य से आलोचना में रचनात्मकता के साथ गर्मजोशी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बत के मसले पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन महत्वपूर्ण था और उन्होंने यह भरोसा जताया कि बदलाव अपरिहार्य है और यह जरूर आएगा।

करीब 1,000 ताइवानी श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने कहा कि उन्हें अध्ययन के साथ बौद्ध धर्म में अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि खुद वह 80 साल का होते हुए भी अब भी नालंदा के प्राचीन गुरुओं के ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ◆

केवल दलाई लामा ही अपने पुनर्जन्म के बारे में निर्णय ले सकते हैं

(तिब्बतनरीव्यू डॉट नेट, 17 अप्रैल, 2015)

ऐसे में जब दलाई लामा की नियुक्ति के बारे में चीन अपने अधिकार के संबंध में झूठे इतिहास और परंपराओं का हवाला दे रहा है, 17वें कर्मापा ने साफ किया है कि इस मामले में निर्णय लेने का हक केवल और केवल दलाई लामा को ही है। रेडियो फ्री एशिया की तिब्बत सेवा को दिए एक इंटरव्यू में तिब्बती बौद्ध परंपरा के कर्मा काग्यू वंश के प्रमुख कर्मापा लामा ने कहा कि उन्हें, "मौजूदा दलाई लामा द्वारा अपने उत्तराधिकारी के बारे में भविष्य लिए जाने वाले निर्णय पर पूरा विश्वास और भरोसा होगा।"

आरएफए पर 15 अप्रैल को आई खबर के अनुसार कर्मापा ने कहा, "इसके बारे में तमाम तरह के कल्पित बयान और अनुमान आ रहे हैं, लेकिन इन सबसे मैं चिंतित नहीं हूं।

29 साल के कर्मापा दिसंबर 1999 में धार्मिक आज़ादी न होने का हवाला देते हुए चीनी शासन वाले तिब्बत से भाग आए थे। वाशिंगटन में दिए गए इस इंटरव्यू में कर्मापा ने कहा कि वैसे तो परंपरागत रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म में जीवित गुरुओं के पुनर्जन्म में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन "मेरा मानना है कि अपने भविष्य के पुनर्जन्म के बारे में निर्णय खुद दलाई लामा ही कर सकते हैं। इसलिए मैं आश्वस्त हूं और मुझे उनके निर्णय में पूरा भरोसा है।"

वैसे तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नास्तिक है, जिसकी धार्मिक मामलों में कोई समझ नहीं है, लेकिन हाल में वह इस बात पर जोर देने लगी है कि यह निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ उनके पास है कि मौजूदा दलाई लामा का पुनर्जन्म कहां होना चाहिए। ◆

चीनी प्रमुख तिब्बत के मठों को अपने दुष्प्रचार के संभावित सहयोगी के रूप में देखते हैं

(तिब्बतनरीव्यू डॉटनेट, 4 अप्रैल, 2015)

अशांत तिब्बत इलाके में चीन सरकार द्वारा नियुक्त मुखिया ने कहा है कि बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों को "दोस्त" समझना चाहिए और तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र (टीएआर) के मंदिरों और मठों को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगंडा केंद्र बनाना चाहिए। समाचार एजेंसी रायटर्स ने यह खबर दी है।

पार्टी की प्रभावी पाक्षिक पत्रिका क्विउशी में लिखे एक लेख में तिब्बत के कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव छेन क्वांगडुओ ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों से आह्वान किया कि वे विज्ञान का 'सम्मान' करें और पार्टी के प्यार की सराहना करें। खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि सरकार टीएआर के 1,700 से ज्यादा मंदिरों और मठों तथा 46,000 भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को 'दोस्त' समझती है जिन्होंने पार्टी के कृपा की सराहना की है। क्विउशी का मतलब होता है, 'सच की तलाश'। इस पत्रिका में छेन ने लिखा है, "मंदिरों और मठों के भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को पार्टी और सरकार के देखभाल एवं गर्मजोशी का व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए, उन्हें पार्टी की परोपकारिता का अनुभव करना चाहिए और पार्टी के शब्दों को सुनना तथा पार्टी के रास्ते पर चलना चाहिए।"

यह सुझाव देते हुए कि भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को सही रास्ते पर चलने के लिए सही मागदर्शन की जरूरत है, उन्होंने लिखा है, "भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों को पार्टी एवं सरकार की नीतियों और सामाजिक प्रगति या तिब्बत में शांति, स्थिरता एवं सौभाग्य को समझने के लिए मंदिरों एवं मठों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है और इसी तरह वैज्ञानिक संस्कृति के सम्मानजनक रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए भी।"

रायटर्स के अनुसार छेन ने इसके पहले 2013 में भी इसी तरह का लेख लिखकर कहा था कि टीएआर के चीनी अधिकारियों को अलगाववाद के खिलाफ 'अभेद्य सुरक्षा' कायम करना चाहिए और भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के प्रति मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ◆

एक अवतार जिस पर नियंत्रण बीजिंग को पसंद है

(हिंदुस्तान टाइम्स, 10 अप्रैल, 2015)

जयदेव रानाडे

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बतियों के बीच दलाई लामा के असर को कम करने में नाकाम रही है।

तिब्बत और दलाई लामा का मसला राष्ट्रपति शी चिनपिंग के नेतृत्व वाले चीनी नेतृत्व की घरेलू प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। पिछले तीन साल में दलाई लामा के पुनर्जन्म के मसले पर ज्यादा ध्यान आकर्षित हुआ है। खासकर पिछले महीने इसे ज्यादा महत्व मिला है, जब दो महत्वपूर्ण बैठकें हुईं–पंद्रह दिन तक चलने वाली नेशनल पीपल्स कांग्रेस (एनपीसी) की बैठक और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष सलाहकार निकाय चीनी जन राजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीसीसी) की बैठक जो मार्च की शुरुआत में हुई।

तिब्बत में समस्या है इसे याद दिलाने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है 5 मार्च को–दो महत्वपूर्ण सम्मेलनों की औपचारिक शुरुआत का दिन–सिचुआन प्रांत के अशांत गावा तिब्बती स्वायत्तशासी क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय तिब्बती महिला नॉर्छुक द्वारा आत्मदाह। गावा तिब्बती स्वायत्तशासी इलाका वर्ष 2009 से ही आत्मदाह के लिए चर्चित स्थान रहा है, तिब्बत में अब तक हुई आत्मदाह की 137 घटनाओं में से 45 नावा में ही हुई हैं।

मौजूदा 14वें दलाई लामा के पुनर्जन्म का मसला पिछले कुछ सालों से चीनी नेतृत्व की चिंता का विषय बना है। अगस्त 2007 में चीन में धार्मिक मामलों के राज्य प्रशासन (एसएआरए) ने कहा कि उच्च लामाओं के पुनर्जन्म को पहचानने और उसे मंजूर करने का अधिकार सिर्फ चीन सरकार को है। इसके बाद से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व ने 358 से ज्यादा पुनर्जन्म को 'मान्यता' दी है, जिनमें भारत में रहने वाले महत्वपूर्ण वंशावली के कई उच्च स्तरीय भिक्षुओं का पुनर्जन्म भी शामिल है। यह तब है, जब 1995 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा स्थापित पंचेन लामा को अब तक तिब्बतियों के बीच लोकप्रियता हासिल नहीं हुई है।

गत दिसंबर माह में 79 वर्षीय दलाई लामा द्वारा बीबीसी न्यूजनाइट कार्यक्रम में दिए एक इंटरव्यू के बाद इस मसले पर सबका ध्यान और आकर्षित हुआ है। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में दलाई लामा ने कहा, "दलाई लामा की संस्था एक दिन खत्म हो जाएगी। इन मानव निर्मित संस्थाओं को खत्म होना चाहिए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई मूर्ख दलाई लामा न आ जाए जो अपनी गरिमा को गिरा दे। यह बेहद ही दुःखद होगा। इसलिए ज्यादा बेहतर यह है कि शताब्दियों पुरानी इस परंपरा को लोकप्रिय दलाई लामा के समय ही बंद कर दिया जाए।"

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों और चीन की आधिकारिक मीडिया ने दलाई लामा की इस टिप्पणी पर अनुमान के मुताबिक ही प्रतिक्रिया दी और तिब्बती बौद्ध धर्म की परंपराओं, खासकर दलाई लामा की संस्था को बनाए रखने पर जोर दिया।

चीन की सरकारी मीडिया ने दलाई लामा पर यह आरोप लगाया कि वह 'एक परंपरा पर अपनी इच्छा थोप रहे हैं।' यह स्वीकार करते हुए कि 'तिब्बती इलाके में दलाई लामा का असर होता है' एक आलेख में यह जोर दिया गया है कि 'पुनर्जन्म को गड़बड़ करने का कोई भी प्रयास' दलाई लामा को अपनी मातृभूमि और धर्म के लिए 'दोहरा विश्वासघाती' साबित करेगा।

इन वक्तव्यों से यह स्पष्ट है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीन के भीतर या बाहर रहने वाले तिब्बतियों को शांत करने या उनके बीच दलाई लामा के असर को सीमित करने में नाकाम रही है। इसके भारत के लिए भी कुछ निहितार्थ हैं। ये मसले लगातार विवादास्पद होते जा रहे हैं, इसलिए यह संभव है कि चीन अब भारत पर दबाव बढ़ाए। यह भारत में तिब्बतियों और दलाई लामा की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों पर केंद्रित होगा और चीन अब तवांग तथा अरुणाचल प्रदेश पर अपने क्षेत्रीय दावों के संबंध में ज्यादा अड़ियल रवैया अपना सकता है। ◆

तिब्बतियों के लिए दलाई लामा एक अगुआ के रूप में क्यों मायने रखते हैं

(तिब्बत डॉट नेट, 1 अप्रैल, 2015)

रॉबर्ट थर्मन

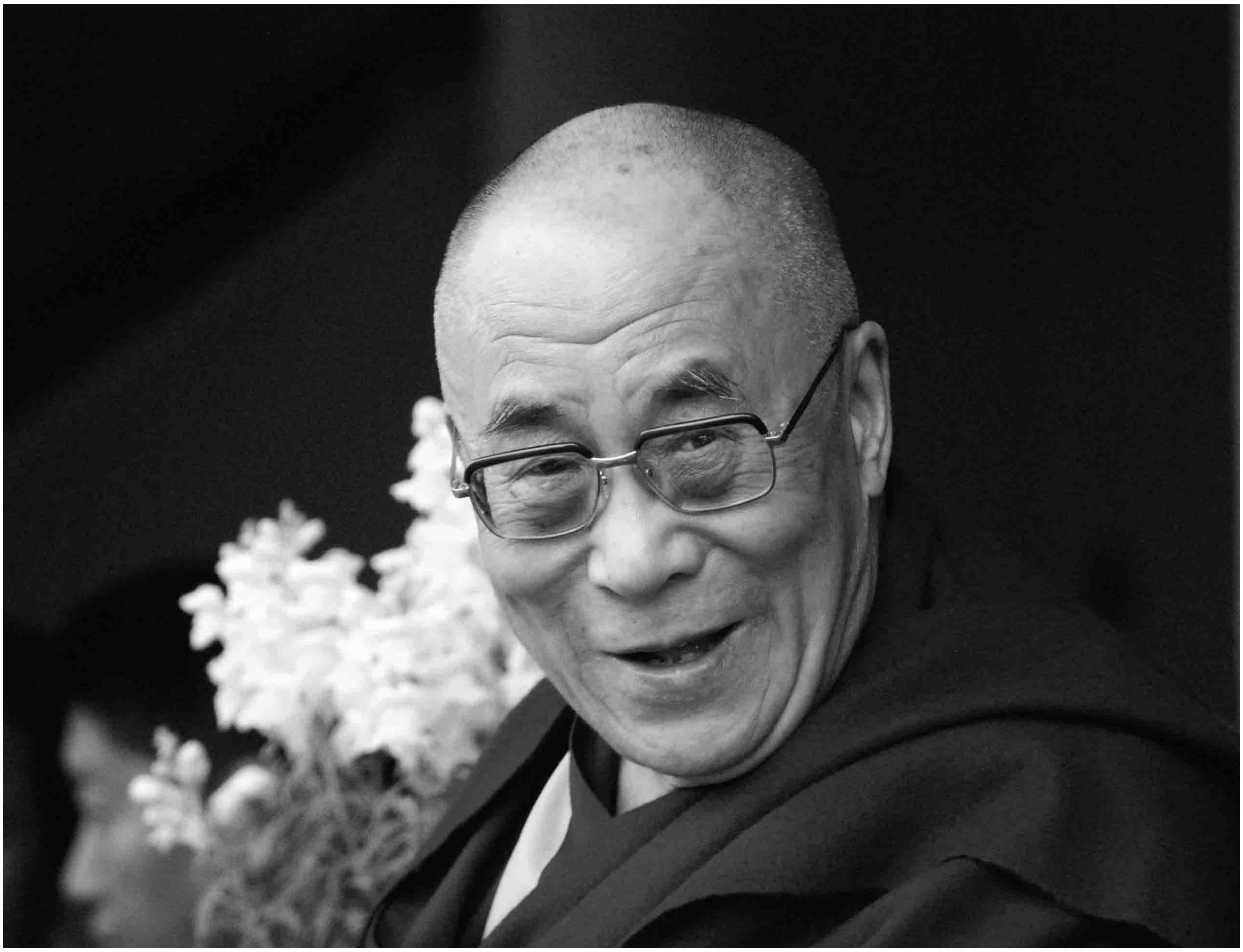

दलाई लामा अब भी निर्वासित तिब्बती युवाओं और तिब्बत में रहने वाले तिब्बतियों को सीमा में रहने और अहिंसा पर चलने के लिए प्रेरित कर पा रहे हैं, इसके बावजूद कि चीन सरकार की दमनकारी नीतियों एवं विनाशक नीतियों के चलते आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने में कमी, धार्मिक आज़ादी के अभाव की वजह और अन्य मानवाधिकार मामलों की वजह से उनके बीच कुंठा काफी ज्यादा है।

दलाई लामा और तिब्बती स्वायत्तता के लिए उनका आह्वान

निर्वासन में आज़ादी से घूम रहे या तिब्बत में भूमिगत रहने वाले कई तिब्बती अब दलाई लामा के नेतृत्व पर सवाल उठाने लगे हैं क्योंकि वह लगातार अहिंसा पर जोर देते रहे हैं और उन्होंने तिब्बत की पूर्ण आज़ादी की मांग, जिसका वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक हकदार है, करने की जगह चीन के भीतर ही स्वायत्तता देने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन अभी तक वे उनका अनुसरण कर रहे हैं और हिंसा के इस्तेमाल से बचे हुए हैं।

स्वायत्ता बनाम आज़ादी की यह पूरी बहस असल में एक आम भ्रम की वजह से है। दलाई लामा कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाते कि हर तिब्बती आज़ादी चाहता है और यह उसका अधिकार है, वह हमेशा यह कहते रहे हैं कि सभी व्यक्ति और सभी देश इसके साथ ही फले–फूले हैं और सभी इसकी प्रमुखता को महत्व देते रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद उन्हें और उनके पड़ोसियों को एक–दूसरे से रिश्ते बनाने होते हैं। उन्हें व्यापार, आदान–प्रदान, सहन करना होता है और एक–दूसरे से जुड़ना होता है। पूर्ण आज़ादी जैसी कोई चीज नहीं होती, हर कोई एक–दूसरे पर निर्भर होता है। इसलिए चीन के भीतर असल स्वायत्तता की मांग करना बस एक व्यावहारिक कदम है।

दलाई लामा चीनियों से अनिवार्य रूप से कहते रहे हैं, "ठीक है, आप तिब्बत पर स्वामित्व चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। तिब्बत प्राकृतिक रूप से आज़ाद है और तिब्बती लोग तिब्बती हैं, चीनी नहीं। लेकिन आप तिब्बत के भविष्य में बड़ी भूमिका निभाने को दृढ़ दिख रहे हो और हमें आधुनिक होने के लिए और उस नुकसान को ठीक करने के लिए आपकी मदद चाहिए जो आपके पूर्व शासकों ने हमारी भूमि का किया है, इसलिए हम स्वेच्छा से आपके महासंघ में शामिल होना चाहते हैं, यह 'एक देश, दो विधान' जैसी व्यवस्था होगी जैसा कि हांगकांग में है और जल्दी ही ताइवान में हो सकता है। जैसा कि हम आपके संघ में अल्पसंख्यक लोग हैं, तो आपका संविधान यह निर्देश देता है कि आप हमें चीनी (हान) औपनिवेशीकरण का हिस्सा नहीं बना सकते। इसलिए एक बार जब आप अपने औपनिवेशिक तथा आंतरिक कब्जे वाली सेनाओं को हटा लेंगे, आप हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पर अपने सैनिक तैनात कर सकते हैं और इसके बाद हमें हमारा अपना आंतरिक बुनियादी कानून रखने दें जैसा कि हांगकांग में है। तब हम भी मतदान करेंगे और अपने देश के लोगों को भी इसके लिए राजी करने का अभियान चलाएंगे कि वे आपके साथ एक वैधानिक, स्वैच्छिक संघ में शामिल होने के लिए मतदान करें। और आप ज्यादा चिंता न करें सिर्फ इसलिए मैं समय से पहले अभी से इस संघ के पक्ष में अपना मत देता हूं।"

तिब्बत की मौजूदा कानूनी एवं ऐतिहासिक स्वाधीनता

मसला यह है कि दलाई लामा को स्वाधीनता के लिए आह्वान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तिब्बत वास्तव में ऐतिहासिक, नैतिक और कानूनी रूप से आज़ाद रहा है। यह हमेशा स्वाधीन रहा है और हमेशा विशाल आकाश के नीचे उन्मुक्त उच्च भूमि रहा है, जिसकी ऊंची चोटियां बर्फ से सजी रहती हैं, जहां विशेष जीन वाले लोग ही सुविधाजनक तरीके से रह सकते हैं क्योंकि करीब तीन मील के उन्नतांश पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उनकी स्वाधीनता न सिर्फ दलाई लामा सहित सभी जीवित तिब्बतियों के दिमाग में बसी हुई है, बल्कि यह किसी के दिमाग में भी हो सकती है जो मौजूदा चीनी सरकारों के दुष्प्रचार और राजनयिक झूठ से परे देखते हैं और इतिहास तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत इस मसले का सतही रिसर्च नहीं करते हैं। सिर्फ इसलिए कि चीन के पास सेना है और वहां उपनिवेशवादी लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि संयुक्त राष्ट्र एवं दूसरे देशों की कार्यकारी शाखाएं डर एवं लालच से इस मसले को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत लाने से बच रही हैं, यह साबित नहीं हो जाता कि चीन का कब्जा वैध है और न ही उसके हास्यास्पद झूठे ऐतिहासिक दावे पर कोई ऐतबार कर सकता है। सच तो यह है कि दुनिया की कई महत्वपूर्ण संसदें–अमेरिकी कांग्रेस, जर्मनी का बुंडेस्टैग, फ्रांस एवं इटली की संसद, कोस्टा रिका की संसद, यूरोपीय संसद–सभी ने अमेरिकी कांग्रेस की तरह का प्रस्ताव पारित किया है जिसमें एकमत से यह कहा गया है कि तिब्बत विदेशी कब्जे वाला एक स्वाधीन देश है। ◆

तिब्बत पर प्रगति

(बिजनेस स्पेक्टेटर, 23 अप्रैल, 2015)

रॉबर्ट बार्नेट

चीनी अधिकारी निर्वासित तिब्बती नेतृत्व के अधिकारियों से पांच साल पहले मिले थे। इसके बाद से चीन–तिब्बत विवाद को हल करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस बीच, चीनी शासन के विरोध में प्रदर्शन जारी है और सौ से ज्यादा तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं। चीन सरकार ने इसकी प्रतिक्रिया में तिब्बती इलाके में लोगों की आवाजाही, पूजा, भाषण और सूचनाओं के प्रवाह पर सख्त अंकुश लगा दिया है और निगरानी का तंत्र भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन इस मसले को हल करने की विफलता की वजह यह नहीं है कि जमीनी स्तर पर तनाव है। इसकी वजह दोनों नेतृत्व का इस बारे में सहमति बनाने की अक्षमता है कि वास्तव में मसला क्या है।

तिब्बत के हालात के बारे में दो प्रमुख विचार हैं। एक विचार के तहत इसे एक अल्पसंख्यक सवाल माना जाता है, जिसमें धार्मिक मतभेदों और आर्थिक तनाव की समस्याओं की वजह से किसी समाज की संरचनात्मक असमानता और बढ़ जाती है। चीनी अधिकारी आमतौर पर इस विचार को मानते हैं, यह जोड़ते हुए कि इस तरह के तनाव बाहरी उपद्रवियों की वजह से और ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा पहलू, अक्सर तिब्बतियों और पश्चिमी लोगों में यह पाया जाता है कि तिब्बत को एक बड़े पड़ोसी ने हड़प लिया है और वह उसके इतिहास को नकार रहा है। चीन में आप यदि इस तरह का विचार रखें तो अचानक सामने वाला बातचीत बंद कर सकता है और संभवतः पुलिस भी आप तक पहुंच सकती है। इन दो विचारों वाले लोगों के बीच परस्पर अविश्वास उनके बीच किसी तरह की बातचीत को असमर्थ बनाती है।

दोनों पक्षों के पास अपने–अपने पहलू को आधार देने के लिए वाजिब साक्ष्य हैं। नस्लीय तनाव वाले विचार के लोगों का समर्थन करने के लिए यह तथ्य है कि 13वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में बीजिंग के शाही दरबार द्वारा तिब्बतियों को अपने अधिकार क्षेत्र में माना जाता था। आज चीन की जनसंख्या में उनका हिस्सा महज 0.4 फीसदी है और इनमें से 80 फीसदी से ज्यादा देहात में रहते हैं (जबकि समूचे चीन में यह अनुपात करीब 50 फीसदी का ही है)। इस विचार के सबसे जानकार लोग भी यह स्वीकार करते हैं कि आंतरिक आव्रजन और तीव्र विकास की वजह से तिब्बति अपनी संस्कृति और भाषा पर गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन वे इसे उसी तरह से मानते हैं जैसे ज्यादातर अल्पसंख्यकों को कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और यह असमान विकास या बाजार की प्रतिस्पर्धा का नतीजा होता है। चीन में परिस्थिति थोड़ी जटिल हो गई है, संस्कृति, धर्म और अभिव्यक्ति पर थोपी गई सीमाओं की वजह से, लेकिन यह अब भी यह काफी हद तक नस्लीय

असंतोष के मानक मॉडल में ही फिट होता है।

लेकिन दूसरे तरीके से देखें तो तिब्बत की परिस्थिति दूसरे अल्पसंख्यक मसलों से अलग है। बीसवीं शताब्दी के ज्यादातर शुरुआती दशकों में तिब्बती पठार का आधा हिस्सा समझौतों पर दस्तखत करने वाला एक अलग देश था। उसकी अपनी सरकार और सामाजिक व्यवस्था थी और उसके द्वारा इतना व्यापक एवं विशिष्ट साहित्य रचा गया जो विश्व विरासत का एक उल्लेखनीय हिस्सा बन गया है, जिसके बारे में हर तिब्बती जानता है। माओ त्से तुंग द्वारा 1950 में कब्जे के लिए अपनी सेना भेजने से पहले बहुत कम चीनी तिब्बती इलाके के बारे में जानते थे और आज भी वहां ऐसे बहुत कम तिब्बती हैं जो तिब्बती बोल या पढ़ सकें।

बीजिंग के लिए तिब्बत के पास कुछ अन्य विशेष गुण हैं। यह सामरिक रूप से एक महत्वपूर्ण इलाका है जो कि चीन के मौजूदा भौगोलिक क्षेत्र का करीब एक चौथाई है। यह तीन परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच में आता है जिनमें से दो–भारत और चीन–तिब्बत सीमा पर लंबे समय से सैन्य तनातनी में शामिल रहे हैं। इसके अलावा तिब्बत का पठार उन नदियों का स्रोत है जो चीन, दक्षिण और दक्षिण–पूर्व के ज्यादातर इलाकों में जल की पूर्ति करती हैं।

तिब्बत का मसला एक और पहलू के हिसाब से अप्रासंगिक हैः फिलिस्तीन, चेचन्या डारफूर जैसे लंबे समय से चलने वाले संघर्षों से तुलना करें तो यहां हिंसा का स्तर असाधारण रूप से कम है।

1950 और 1960 के दशक में जब तिब्बती सेना या गुरिल्ला चीनी सैनिकों से लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें हजारों तिब्बतियों की मौत हो गई। हालांकि, पिछले 40 साल में अशांति सड़कों पर विरोध प्रदर्शन में बदल चुकी है, लेकिन बीच–बीच में इसने सिर्फ छह–सात बार ही शहरी दंगे का रूप लिया है। पिछले चार दशकों में तिब्बतियों द्वारा की जाने वाली राजनीतिक हिंसा में महज 20 तिब्बतियों की मौत हुई है, वह भी ज्यादातर 2008 की नृसंश घटना में। इसी दौरान सुरक्षा बलों द्वारा करीब 300 से 400 तिब्बती मारे गए हैं।

हिंसा की यह कम घटनाएं काफी हद तक इस वजह से हैं क्योंकि दलाई लामा अहिंसा पर जोर देते रहे हैं, लेकिन उनकी मौत के तत्काल बाद स्थिति पलट सकती है। लेकिन यह उन कई संकतों में से एक है कि इस समस्या का समाधान अब भी संभव है। हर पक्ष के पास ऐसा अविवादित नेता है जो एक समझौते पर दस्तखत कर सकता है, कमजोर पक्ष लंबे समय से समझौते की जरूरत पर सहमत रहा है और दोनों पक्ष–सिद्धांततः–केवल एक चीज पर उलझे हुए हैं तिब्बतियों को स्वायत्तता किस हद तक होनी चाहिए। इसके अलावा, दुनिया भर के टकराव वाले क्षेत्रों से तुलना करें तो तिब्बत का मौजूदा भेदभाव बहुत मामूली है। यह विवाद के ऐसे लक्षण हैं जो कि–कम से कम फिलहाल–राजनीतिक हल निकालने के दायरे में हैं।

वर्ष 2018 में जब चीन का मौजूदा नेतृत्व अपने दूसरे कार्यकाल में प्रवेश करेगा, तो वह संभवतः कई विरोधी हित समूहों को हटा चुका होगा और तिब्बत के मामले में हू जिनताओ युग की नीति की डेडवेट विरासत को साफ कर चुका होगा। नए और युवा नेता सामने आ चुके होंगे जिसे उसने पदों पर आने के लिए तैयार किया है, उन्हें खुला हाथ दिया जाएगा यह निर्णय करने को कि सुधारों को लागू किया जाए। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिस पर निर्वासित तिब्बती समाधान निकालने की उम्मीद बनाए रखने के लिए दांव लगा रहे हैं।

लेकिन कई कारकों की वजह से लगता है कि समाधान थोड़ा मुश्किल है। ज्यादातर पश्चिमी सरकारों ने चीन की धमकाने वाले शैली की राजनय से निपटने में अनाड़ीपन दिखाया है और अपनी यह सुविधाजनक स्थिति खो दी है जिसे वे कभी बातचीत से हल निकालने को प्रोत्साहित करने के लिए रखते थे। अब केवल अमेरिका, भारत और ताइवान के पास ही इस सवाल पर अपना असर रखने का कोई मौका है। 1980 के दशक से ही दुनिया का समर्थन हासिल करने में दलाई लामा की सफलता की वजह से ही वर्ष 2002 से 2010 के बीच चीन के साथ दस दौर की प्रारंभिक वार्ता हो चुकी है। लेकिन अब समय बहुत कम बचा है, (वह इस साल 80 वर्ष के हो रहे हैं), उन्हें एक प्रभावी उत्तराधिकारी नेता तलाशने की सख्त जरूरत है और आत्मदाह जैसे हाल के मसलों पर वह हिचकिचाहट में रहे हैं, जिन पर वह रोक लगाने का आह्वान करने में असफल रहे हैं।

चीनी पक्ष के सामने ज्यादा बाधाएं दिख रही हैं, जैसे कि वहां के अफसरशाही में अब भी कट्टरपंथ जड़ जमाए हुए है। ऐसी नीतियां लागू करने का उसका लंबा इतिहास रहा है जिसने उसके प्रमुख अल्पसंख्यकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की जगह और बदतर ही बनाया है। लेकिन उसे ऐसी हर चीज से अब बचना होगा जो कि बाहरी दबाव से दिया गया रियायत जैसा दिख रहा हो।

चीन की तिब्बत की रणनीति में आखिरकार सफलता के कुछ लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। पिछले 30 साल से चीन वहां बुनियादी ढांचे और आर्थिक तरक्की के लिए धन झोंक रहा है, इस उम्मीद में कि इससे तिब्बती भी राजनीतिक अशांति में शामिल होने के जोखिम को देखते हुए अर्थव्यवस्था में भागीदारी में अपनी रुचि दिखाएंगे। बहुत से शहरी तिब्बती अब संपन्न हैं और ग्रामीणों की आय बढ़नी शुरू हो गई है। इस आर्थिक तरक्की का अल्पकालिक रूप से राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे चीन द्वारा किसी हल की दिशा में कदम बढ़ाने में और देरी तथा कम उत्साह ही रहेगा।

इन बाधाओं के बावजूद, चीनी नेतृत्व को यह तय करना होगा कि तिब्बत मसले पर बातचीत से हल निकालना उसके हित में भी होगा। लेकिन इसे सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि तिब्बती और चीनी नेता तिब्बत मसले के हल पर एक–दूसरे के विचार को मान्यता दें, दोनों ही तरह से, नस्लीय तनाव वाले एक इलाके के रूप में और एक ऐसे स्थान पर जिसका अनूठा एवं विशिष्ट इतिहास रहा है।

(रॉबर्ट बार्नेट, न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में आधुनिक तिब्बती अध्ययन के निदेशक हैं।) ◆

दलाई लामा को चीन में मिला अनुभव और उसका असर

(हफिंगटन पोस्ट, 15 अप्रैल, 2015)

थुबतेन सामफेल

अब यह खुला रहस्य है कि चीन के नेतृत्व और कारोबारी हलकों तथा आम जनता में दलाई लामा के प्रति सम्मान किस कदर बढ़ रहा है। चीन के बेहद अमीर कम्युनिस्ट बौद्धों के बारे में बीबीसी की खास रिपोर्ट इसका नवीनतम प्रमाण है।

तिब्बती नेता के बारे में विद्वानों ने एक पहलू पर कम गौर किया है कि उनका उन क्रांतिकारी नेताओं से गहन संपर्क रहा है जिन्होंने आधुनिक चीन का सृजन किया है। दलाई लामा करीब एक वर्ष तक 1954 से 1955 के बीच चीन में रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चीनी भाषा सीखी और अपने चीनी मेजबानों द्वारा बताए गए समाजवाद के आदर्श को भी जाना। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि तिब्बती आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता दलाई लामा, चेयरमैन माओ त्से तुंग सहित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई शीर्ष नेताओं से मिले और दलाई लामा के अनुसार माओ ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसा 'एक पिता अपने पुत्र के साथ करता है।" उनके मेजबानों ने उन्हें आधुनिक चीन की खूब सैर कराई ताकि तिब्बती नेता समाजवाद के फायदों को अपने मातृभूमि तक पहुंचाएं। उन्होंने यह देखा कि चीनी नेताओं ने अपने विशाल एवं पिछड़े देश को एक आधुनिक एवं समतावादी समाज बनाने के लिए किस तरह का प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया है।

नया समाजवादी चीन दलाई लामा के विचारों और सोचने के तरीके में किस तरह का बदलाव ला पाया? क्या इस अनुभव ने बाद में दुनिया के बारे में उनके विचार और निर्वासन में उनके द्वारा दिए गए प्रशासन पर असर डाला?

तब दलाई लामा और चीन के लिए भी दुनिया नई और ताजी थी। वह तब 19 साल के ही थे, युवावस्था की शुरुआत में, और चीन में जो नई दुनिया उन्होंने बनते देखी उसके बारे में खुले विचार रखते थे। चीन के लिए यह दौर एक नई शुरुआत का था, पश्चिमी साम्राज्यवाद के अपमान, कमजोर हो चुके सेनापति, गृह युद्ध, जापानी आक्रमण तथा व्यापक रूप से फैले एवं पंगु कर देने वाले भ्रष्टाचार की एक शताब्दी के बाद। दलाई लामा ने चीन का दौरा ऐसे समय में किया जब देश में क्रांतिकारी जज्बा चरम पर था, जब एक न्यायोचित और बराबरी का समाज बनाने की उसकी सामूहिक दृढ़ता वैचारिक पागलपन और भौतिक रूप से नरसंहार तक पहुंच गई थी। यह एक ऐसा

दलाई लामा (दाएं) और पंचेन लामा (बाएं) 1955 में माओ त्से तुंग से मिलते हुए। परमपावन शांति वार्ताओं के लिए चीन गए थे और उन्होंने माओ त्से तुंग से मुलाकात की।

समय था जब नए चीन ने तिब्बती नेता को उसका बेहतर पक्ष दिखाया था।

माओ त्से तुंग के व्यक्तित्व वाले नए चीन ने तिब्बत के राजनीतिक नेता और उसके सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु को यह भी दिखाया कि यह तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए कैसी दोहरी भावना रखता है। दलाई लामा ने इस मसले की अपनी आत्मकथा माइ लैंड, माइ पीपल में चर्चा की है, "कुछ दिनों के बाद मुझे माओ त्से तुंग का एक संदेश मिला कि वह एक घंटे में मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद किसी वजह से ही उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म एक अच्छा धर्म है और भगवान बुद्ध, भले एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने लोगों की दशा सुधारने के सवाल पर काफी अच्छे विचार रखे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देवी तारा एक दयालु महिला थीं। कुछ मिनट रहने के बाद वह चले गए। मैं उनकी टिप्पणियों से काफी चकित था और समझ नहीं पा रहा था कि किस वजह से उन्होंने ऐसा कहा है।"

माओ ने अपनी अंतिम मुलाकात में जिस तरह की टिप्पणियां की उसने दलाई लामा को अनुमान से ज्यादा चकित कर दिया था। उन्होंने लिखा है : "इस जबर्दस्त व्यक्तित्व से मेरा अंतिम साक्षात्कार मेरी चीन यात्रा की समाप्ति के समय हुआ था। मैं नेशनल एसेम्बली की स्थायी समिति की एक बैठक में था, जब मुझे यह संदेश मिला कि वह अपने घर पर मुझसे मिलना चाहते हैं। तब तक मैं चीनी प्रांतों का दौरा पूरा कर चुका था और उन्हें सच्चे

तरीके से यह बता सकता था कि मैंने जिन विकास परियोजनाओं को देखा है उनमें मेरी बहुत रुचि रही और मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। इसके बाद उन्होंने मुझे लोकतंत्र के असली स्वरूप के बारे में लंबा भाषण देना शुरू किया और मुझे सलाह दी कि जनता का नेता कैसे बना जाता है और उनके सुझावों पर अमल कैसे किया जाता है। इसके बाद वह अपनी कुर्सी पर थोड़ा झुककर मेरे करीब आए और धीरे से बोलेः मैं आपको अच्छी तरह से समझता हूं। लेकिन निश्चित रूप से धर्म जहर है। इसमें दो भारी खामियां हैं। यह नस्ल को दमित करता है और दूसरा, यह किसी देश की प्रगति को धीमा करता है। तिब्बत और मंगोलिया दोनों इस जहर से पीड़ित हैं।"

मार्क्स की यह सूक्ति कि धर्म जनता के लिए अफीम है, उस सबको बेकार कर देती है जो माओ बौद्ध धर्म के प्रति व्यक्तिगत सम्मान या संवेदनशीलता दिखाते थे। सांस्कृतिक क्रांति से पहले और उसके दौरान कम्युनिस्टों का कोप धर्म पर ही हुआ। उन्होंने मठों को खंडहर में बदल दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और भिक्षुओं का चोला उतरवा लिया गया। यह नए चीन द्वारा अफीम के धुंए से समाजवाद को दूषित होने से बचाने का प्रयास था। तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म को नष्ट करने का जबर्दस्त राजनीतिक दुष्परिणाम हुआ। एक ही आसमान में दो सूरज नहीं रह सकते थे। बौद्ध धर्म को समाजवाद की किरणों के सामने पिघल जाना ही था।

इन सबके बावजूद दलाई लामा ने चीन में जो समाजवादी विचार सीखे उनका उन पर असर बना रहा। स्थानीय रूप से कार्य करने और वैश्विक रूप से सोचने की अपनी सार्वभौमिक जिम्मेदारी की अवधारणा के बारे में बताते हुए वह कहते हैं, "बौद्ध धर्म के पालन में हमें अहिंसा और सभी तरह के उत्पीड़न को खत्म करने के विचार की आदत है क्योंकि हमें किसी को भी भेदभावपूर्वक नुकसान न पहुंचाने या उसे नष्ट न करने की आदत है। यद्यपि हम यह नहीं मानते कि पेड़ों या फूलों में दिमाग होता है, फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। इसलिए हम मानवता और प्रकृति दोनों के लिए सार्वभौमिक जवाबदेही की भावना को साझा करते हैं।"

कोई भी जो यह सोच सकता है कि इस तरह की सोच बौद्ध पृष्ठभूमि से आई होगी, सभी चीजों के परस्पर निर्भरता की बौद्ध धारणा से। जी नहीं, दलाई लामा ने 2007 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय इसे स्पष्ट करते हुए कहा था। यह विचार कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से भी आया है, दुनिया के मेहनती श्रमिकों और खेतिहारों से जो दूसरे पीड़ित कामगारों और खेतिहरों के प्रति एकजुटता की भावना दिखाते हैं।

वर्ष 1979 में दलाई लाम ने शिक्षित युवा निर्वासित तिब्बतियों के एक समूह द्वारा तिब्बती कम्युनिस्ट पार्टी (टीसीपी) की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्वासन की तिब्बती कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत में रहने वाले उन तिब्बतियों के साथ एक सेतु का काम करेगी जो तिब्बत में समाजवादी विचारों एवं आदर्शों के समर्थक हैं। लेकिन निर्वासित तिब्बतियों और तिब्बत में उनके हमवतन लोगों के बीच यह वैचारिक सेतु ढह गया, जब टीसीपी ने अपने कम्युनिस्ट संगठन को बंद करने का निर्णय लिया।

लेकिन दलाई लामा के साथ चीन का जो अनुभव दूरगामी असर छोड़ सका, वह था चीनी जनता के साथ संपर्क बनाने की उनकी इच्छा और समर्थता। खासकर 2008 में समूचे तिब्बत में फैल गई शांतिपूर्ण जनक्रांति के बाद चीनी लोगों से संपर्क बनाने की यह जरूरत और प्रबल हो गई, क्योंकि चीनी प्रशासन ने अपनी आग उगलने वाली मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इसे तिब्बतियों और चीनियों के बीच के नस्लीय बैर की तरह प्रचारित किया। चीनी प्रशासन ने राजकीय दमन के तहत ही एक तरह से चीनी जनता के बीच बने जबर्दस्त जनरोष को निरीह अल्पसंख्यक तिब्बतियों के खिलाफ इस्तेमाल किया।

इसे देखते हुए तिब्बती नेताओं ने इसकी अनिवार्यता समझी कि खुद पहल करके चीनी विद्वानों और विद्यार्थियों के बीच तिब्बती स्वतंत्रता संघर्ष की प्रकृति को समझाया जाए। मध्यम मार्ग नीति तिब्बत के स्वाधीनता की मांग नहीं करती। इसके तहत चीन जनवादी गणराज्य के संविधान के भीतर ही एकल प्रशासन वाले असल स्वायत्तता की मांग की गई है। चीनियों तक पहुंचने के उनके प्रयासों का नतीजा भी सामने आने लगा है। वह लगातार बढ़ती संख्या में चीनी नागरिकों के बीच भरोसा और सम्मान हासिल करने में सफल रहे हैं। सच तो यह है कि बहुत से चीनी नागरिक ऐसे हैं जो चीन में दलाई लामा की आवाज को उठा रहे हैं। चीन के सेंसर से बचते हुए चीन के इंटरनेट चैटिंग समुदाय में तिब्बत के प्रति चीनी समर्थन और सहानुभूति देखी जा सकती है। इस साल मार्च में यूट्यूब पर पोस्ट की गई और हांगकांग में दिखाई गई एक फिल्म 'द डायलॉग' में यह खुलासा होता है कि लगातार बढ़ती संख्या में मुख्यभूमि चीन के युवा चीनी मेल–मिलाप और पारस्परिक भरोसे के दलाई लामा के संदेश को अपना रहे हैं। डायलॉग का निर्माण एक लेखक वांग लिशियांग द्वारा किया गया है जो बीजिंग में रहते हैं और उनकी पत्नी सेरिंग वुएजर तिब्बत पर लिखने वाली एक सक्रिय ब्लॉगर हैं। यह फिल्म उन दो संवादों के आधार पर बनी है जो दलाई लामा और चीन के नेटिजन के बीच 2010 में आयोजित किए गए थे। बाद में उन्होंने दलाई लामा और दो चीनी मानवाधिकार वकीलों शेनझेन के तेंग बियाओ और बीजिंग के जियांग तियानयोंग के बीच वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग आयोजित कराया था। दोनों मानवाधिकार वकीलों और उनके हमवतन लोगों ने दलाई लामा से हिमालय के दोनों तरफ रहने वाले तिब्बतियों की चिंताओं और अधीरता से जुड़े सवाल पूछे थे। तिब्बती नेता ने जिन सवालों के जवाब दिए थे उनमें उनका संभावित आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, क्या उनके गुजर जाने के बाद तिब्बती अहिंसा के प्रति दृढ़ रह पाएंगे, तिब्बत का मसला कैसे हल हो सकता है, तिब्बती स्वायत्तता की प्रकृति क्या होगी और तिब्बतियों तथा चीनियों के प्रति रिश्ता किस तरह का होगा। करीब 1,543 चीनी नागरिकों ने 300 से ज्यादा सवाल किए थे। सेंसर के दखल हो जाने से पहले इनमें से 12,771 चीनी नागरिकों ने 10 बेहतरीन सवालों के लिए मतदान भी किया था।

(थुबतेन सामफेल, तिब्बत नीति संस्थान के निदेशक हैं) ◆